

## IL & FS संकट

### संदर्भ

- ग्रांट थोर्नटन के कर्ज में डूबी आइएल एंड एफएस समूह के बही-खातों के विशेष ऑडिट के दौरान 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के लेन-देन में कई वित्तीय अनियमितताएं चिन्हित की हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे 18 मामले हैं जहां अंततः कर्ज ऐसे कर्जदारों को दिए गए जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय दबाव में थे। ये सभी चीजों सार्वजनिक थीं। इसमें कहा गया है कि जोखिम टीम के नकारात्मक आकलन के बावजूद 2,400 करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए।
- रिपोर्ट में 10 बड़ी विसंगतियों, अनियमित लेन-देन तथा प्रत्येक सौदे की राशि का जिक्र किया गया है। इनमें कुल मिलाकर यह 13,290 करोड़ रुपए के लेन-देन हुए थे। कई ऐसे मामले पाए गए हैं जहां कुल मिला कर 541 करोड़ रुपए के कर्ज तो अल्पकालीन उद्देश्य के लिए गए थे लेकिन ऐसा लगता है कि उसका उपयोग दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए किया गया।
- रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2018 में धन की कमी बहुत बढ़ गई थी। आइएल एंड एफएस के पूर्व चेयरमैन रवि पार्थसारथी ने 21 जुलाई 2018 को इस्तीफा दिया था। ऑडिट कंपनी ने यह भी पाया कि 16 मामलों में 1,922 करोड़ रुपए के जो कर्ज दिए गए, उसमें ब्याज धन की लागत से भी कम था। नकदी संकट से गुजर रही कंपनी ने अगस्त के अंतिम सप्ताह से बैंक कर्ज तथा अन्य कर्ज भुगतान में चूक करना शुरू किया।
- (IL & FS) – इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कर्ज उपलब्ध कराता है। यह 30 साल पुरानी कंपनी है। इसकी कई सहायक कंपनियां हैं, इसने देश में 1.8 ट्रिलियन रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटाने और उन्हें पूरा करने में मदद की है, इसमें चेन्नई-नाशरी सुरंग शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम इसका सबसे बड़ा प्रमोटर है, इसके अलावा एसबीआई सहित कई बैंक और वित्तीय संस्थान भी इसके प्रमोटरों में शामिल हैं, कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पर काम करती है, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कई तरह की सेवाएं देती हैं।

### क्या है समस्या?

- IL & FS नकदी की कमी से जूझ रही है, एक तरफ नए प्रोजेक्ट नहीं मिलने से कंपनी पर दबाव बढ़ा है तो दूसरी तरफ ऊंची दरों पर छोटी अवधि के लोन लेने से कंपनी की वित्तीय हालत खस्ती हो गई है, कई परियोजनाओं में देरी होने से भी कंपनी की मुश्किलें बढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद से कंपनी को सरकार से मिलने वाला 90 अरब रुपये फंसा हुआ है।
- कर्ज का भारी बोझ अगले छह महीने में IL & FS को करीब 50 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाना है, इसका कुल कर्ज बढ़कर करीब 12.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, अगस्त में कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका सकी। कमर्शियल पेपर के जरिए यह कर्ज जुटाया गया था, कमर्शियल पेपर जारी कर कंपनियां छोटी अवधि के लिए कर्ज जुटाती हैं,

### निवेशकों पर पड़े असर?

- म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीमों में कमर्शियल पेपर में निवेश करती हैं, बैंक एफडी पर कम ब्याज के चलते हाल में कमर्शियल पेपर की लोकप्रियता बढ़ी है। IL & FS की खराब वित्तीय हालत के चलते इसके कमर्शियल पेपर में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंडों की चिंता बढ़ गई है, कुछ फंडों ने इसके चलते अपने पोर्टफोलियों की वैल्यूएशन घटा दी है, म्यूचुअल फंडों के अलावा पेंशन फंड मैनेजर्स और बीमा कंपनियों ने भी IL & FS की सिक्योरिटी में निवेश किया है, इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका असर इनके निवेशकों और पॉलिसीधारकों पर भी पड़ेगा। IL & FS इंटर-कॉर्पोरेट डिफॉल्ट पर भी डिफॉल्ट कर चुकी है, ये भी छोटी अवधि में कर्ज जुटाने के जरिया हैं, वित्तीय कंपनियों का पैसा डूबने का डर IL & FS को सिडबी और मुद्रा सहित कई वित्तीय संस्थानों ने कर्ज दिया है, अगर कंपनी की हालत नहीं सुधरती है तो इस कर्ज की अदायगी को लेकर भी समस्या शुरू हो सकती है।

### संसदीय समिति और जांच आयोग

- संसद की एक समिति ने आईएलएंडएफएस संकट एवं ऋण साख निर्धारण करने वाली एजेंसियों (सीआरए) की भूमिका की जांच के लिये एक जांच आयोग के गठन का बुधवार को सुझाव दिया। वित्त मामलों से जुड़ी संसद की

स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रपट में कहा है कि सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है और कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है एवं राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) इस मामले को देख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, “समिति एक समग्र जांच आयोग के गठन की सिफारिश करती है, जो सभी पहलुओं को देखेगा एवं सीआरए की भूमिका की जांच करेगा, जिन्होंने संकट से कुछ पहले संस्थाओं की रेटिंग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम सहित IL & FS के संस्थागत शेयरधारकों की भूमिका की जांच भी की जाएगी।”

- मौजूदा केन्द्र सरकार का मानना है कि इसके लिए यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस जिम्मेदार है, यूपीए कार्यकाल में पॉलिसी पैरालिसिस के चलते कई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। जिसके चलते IL&FS कर्ज के बोझ में दब गया।
- IL&FS के खिलाफ केन्द्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी- NCLT) का दरवाजा कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 241 के साथ सेक्शन 242 के तहत खटखटाया है, केन्द्र सरकार ने एनसीएलटी से कंपनी के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हट करके नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने की मंजूरी मांगी है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर लीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL & FS) के डिफॉल्ट के बाद बाजार में उभरते संकट पर काबू पाने के लिए सरकार ने दो प्रमुख कदम उठाए, पहला एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाकर कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ लिया और नए मैनेजमेंट की तैनाती कर दी और दूसरा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑफिस यानी SFIO से कंपनी के खातों की जांच के आदेश दिए हैं।

### NBFC कंपनियों का बिजनेस मॉडल

IL&FS समेत देश की सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) का बिजनेस मॉडल दरअसल बॉण्ड से सस्ता पैसा जुटाकर महंगा लोन देने का है। इनके पास डिपॉजिटर्स की सस्ती पूंजी नहीं होती, ऐसे समय में जब नकदी के अभाव में बॉण्ड बिकना मुश्किल हैं, तो कंपनी को उभारने के रास्ते कहां से निकलेंगे, खराब बाजार में बॉण्ड की प्लेसमेंट ऊंची दर (यील्ड) पर होती है, बॉण्ड का पूरा बाजार भरोसे पर चलता है, यील्ड का बढ़ना न केवल IL&FS या एनबीएफसी सेक्टर को चोट पहुंचाएगा बल्कि पूरे बाजार के समीकरण को बिगाड़ देगा।

### आगे की राह

सिडबी के 1000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के बाद IL&FS ने आय के कुछ संभावित रास्ते बताए थे, जिनमें मुकदमों में फंसा कंपनी का 16000 करोड़ रुपया, 30000 करोड़ रुपए के मूल्य वाली कंपनी की 25 सम्पत्तियों की बिक्री और राइट इश्यू के जरिए 4500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, IL&FS के संकट में फंसने की एक बड़ी वजह भी दरअसल छोटे समय के लोन लेकर लंबी अवधि के प्रोजेक्ट फाइनेंस करना भी है।

### मुख्य परीक्षा प्रश्न

- बैंकिंग या गैर बैंकिंग फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशनों के धराशायी होने का दुष्प्रभाव सार्वजनिक परियोजनाओं के साथ देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ता है जिससे देश में राष्ट्रीय वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। इस कथन के संदर्भ में ऐसे संस्थाओं के रेगुलेशन हेतु विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों तथा RBI की नीतियों पर चर्चा करें -

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

**निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**

1. IL&FS संकट से निपटने के लिए सरकार ने उद्योगपति उदय कोटक के नेतृत्व में बोर्ड गठित किया।
  2. IL&FS पर वित्तीय मामलों की स्थाई समिति के अध्यक्ष विरप्पा मोईली थे।
  3. IL&FS को भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (ppp) मॉडल का जनक माना जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है?
- (a) 1 और 2
  - (b) 2 और 3
  - (c) 1 और 3
  - (d) उपर्युक्त सभी